Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 23/August/2023 IJRAW: 2023; 2(9):127-131 Accepted: 25/September/2023

भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था: अवसर एवं चुनौतियाँ

*[1]Sarita Singh

*[1]Assistant Professor, Department of Economics, MSJ Government College Bharatpur, Rajasthan, India.

सारांश

भारत में कैशलेस लेनदेन भौतिक नकदी के उपयोग को कम करके कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का एक प्रयास है। कैशलेस लेनदेन बैंकिग प्रणाली में एक नवाचार के रूप में प्रचलन में लाया गया था।अध्ययन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल मुद्रा के उपयोग में भारत की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करना और उन चुनौतियों और अवसरों का पता लगाना है जो भारत में कैशलेस लेनदेन से जुड़ी हैं। विमुद्रीकरण की घोषणा (2016) भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। शोध अध्ययन में कैशलेस लेनदेन के विभिन्न माध्यमों का वर्णन किया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था से काले धन, जाली नोटों पर अंकुश लगाने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, नकदी संबंधी डकैती को कम करने और हमारे देश के आर्थिक विकास में सुधार करने में मदद मिलेगी। प्रमुख चुनौतियाँ जो नीति के कार्यान्वयन में बाधा बन सकती हैं, वे हैं डिजिटल निरक्षरता, इंटरनेट कनेक्टिविटी की अपर्याप्त ग्रामीण पैठ, अपर्याप्त बैंकिंग बुनियादी ढांचा, ग्रामीण ग्राहकों के बीच जागरूकता की कमी, असंगठित स्वदेशी बाजारसाइबर धोखाधड़ी, डिजिटल भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता की कमी है। अध्ययन में सुझाव दिये गये हैं कि अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग करना शुरू करना चाहिए जो कि कैशलेस अर्थव्यवस्था या कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को स्थापित करेगा।

मुख्य शब्द: कैशलेस लेनदेन, काला धन, आर्थिक विकास, डिजिटल भुगतान, कैशलेस अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना

अर्थव्यवस्था को कैशलेस अर्थव्यवस्था में बदलना अब एक विश्वव्यापी चुनौती बन गया है। अधिकांश देश पहले ही खुद को कैशलेस अर्थव्यवस्था में बदल चुके हैं। कैशलेस इकॉनमी वह है जहां लेनदेन डिजिटल मोड या अन्य मोड में होता है और मुद्रा, सिक्कों या भौतिक नकदी का कम उपयोग होता है। इंटरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा जैसी प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ लोगों के लिए कहीं भी और किसी भी समय लेनदेन करना अधिक सुविधाजनक हो गया है। भारत में वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के बाद डिजिटल लेनदेन के उपयोग में भारी वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा विमुद्रीकरण के कदम से लोगों को अपने दैनिक लेनदेन में डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार द्वारा बहुत सारे उपायों और विकास के साथ, भारत कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालाँकि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कई सामाजिक-आर्थिक अड़चनें हैं।

प्रत्येक अर्थव्यवस्था, जिसे किसी अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार के भौतिक लेनदेन के लिए कानूनी मानक के रूप में परिभाषित किया जाता है, कार्य करने के लिए नकदी पर निर्भर करती है। पारदर्शिता बढ़ाने, वित्तीय चैनलों के माध्यम से धन के प्रवाह की दक्षता में सुधार लाने और काले धन पर रोक लगाने के लिए अर्थव्यवस्था में कैशलेस लेनदेन आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर कृषि आधारित होने से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के प्रभुत्व में स्थानांतरित हो रही है। एक अर्थव्यवस्था को "कैशलेस" तब कहा जाता है जब लेन-देन मुख्य रूप से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड भुगतान उपकरणों द्वारा समर्थित होते हैं, न कि नोट, सिक्कों या किसी अन्य भौतिक रूप से। एक "नकदी रहित अर्थव्यवस्था" वह है जिसमें सभी लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्यक्ष डेबिट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन और भारत की तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रीयल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) जैसी भुगतान प्रणालियों के माध्यम से होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अर्थव्यवस्था की बेहतरी के उद्देश्य से पूरे देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे नोटबंदी और आधार पंजीकरण | इसकी नींव हमेशा "कैशलेस सोसाइटी" के लिए प्रयासरत थी और हमने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान उस दिशा में काफी प्रगति की। महामारी जिसने सामाजिक बहिष्कार, लॉकडाउन और डिजिटल भुगतान और मीडिया पर अत्यधिक निर्भरता का कारण बना। एटीएम, एमआईसीआर, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के उपयोग के साथ, भारत 20वीं सदी के अंत से उत्तरोत्तर एक कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर विकसित हो रहा है। इन दिनों, आप मोबाइल वॉलेट, रिचार्ज कूपन, यूपीआई, एनएफसी,

*Corresponding Author: Sarita Singh

क्यूआर कोड आदि का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। दरअसल, डिजिटल तकनीक को अपनाने के मामले में भारत ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है।सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था में काफी वृद्धि हुई है। इसके प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था और समाज में बदलना है जो प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम है। महामारी के कारण देश ने पिछले दो वर्षों में डिजिटल तकनीक को बहुत तेजी से अपनाया है। फिनटेक उद्योग के विकास के साथ डिजिटल भुगतान विधियों की स्वीकृति और सामान्यीकरण में सुधार हुआ है। वे अब अधिक सुरक्षित, सटीक, सख्त सरकारी नियमों के अधीन हैं, और औसत व्यक्ति के उपयोग के लिए आसान हैं। वित्तीय समावेशन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, और जैसे-जैसे इस क्षेत्र को डिजिटलीकरण और वित्तीय सहायता दी जा रही है, डिजिटल जागरूकता बढ़ रही है। देश भर में लाखों बैंक रहित और कम बैंक वाले व्यक्ति वित्तीय समावेशन से आशा प्राप्त कर रहे हैं, जो उन्हें अधिक संभावनाओं वाले आकांक्षी जीवन की दिशा में इंगित कर रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल चैनलों का उपयोग करके किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले सभी वित्तीय लेनदेन को कैशलेस अर्थव्यवस्था में होने के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्रत्येक व्यावसायिक लेनदेन में अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान शामिल है, प्रौद्योगिकी के लिए धन्यवाद। कैशलेस अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य वर्तमान में होने वाले अपंजीकृत लेनदेन को कवर करना है। समानान्तर काले धन की अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार को कम करने और देश को स्थानांतरित करने के लिए आरबीआई और भारत सरकार प्रीपेड उपकरणों और कार्ड सहित डिजिटल भुगतान उपकरणों या मोड को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था में भौतिक नकदी के उपयोग को कम करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। अधिक पारदर्शी प्रणाली की ओर। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य यह परिभाषित करना है कि कैशलेस प्रणाली क्या है और उन प्रमुख बाधाओं को देखना है जिन्हें भारतीयों को कैशलेस होने के लिए सामना करना होगा। अध्ययन से पता चलता है कि भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने को सही दिशा में एक कदम माना जा सकता है क्योंकि यह कई फायदे प्रदान करता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार और विकास में सहायता करता है।

कैशलेस अर्थव्यवस्था

आधुनिक तकनीक के युग में, भारत सरकार मौजूदा भौतिक मुद्रा प्रथा को बदलकर कैशलेस अर्थव्यवस्था के विकास के माध्यम से डिजिटलीकरण पर जोर देने की कोशिश कर रही है। 'कैशलेस इकोनॉमी' शब्द का अर्थ एक ऐसी वित्तीय स्थिति से है जिसमें लोगों द्वारा लेनदेन करने के लिए कोई तरल धन या कागजी मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता है। कैशलेस इकोनॉमी एक वित्तीय प्रणाली है जिसका उद्देश्य अधिक इलेक्ट्रॉनिक-आधारित लेनदेन को प्रोत्साहित करते हुए कुल भौतिक मुद्रा को कम करना है, न कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में चल रहे नोटों या सिक्कों को समाप्त करना। अधिक विशेष रूप से, कैशलेस अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जहां करेंसी नोटों, सिक्कों या भौतिक नकद धन के रूप में वित्तीय लेनदेन नहीं किया जा रहा है। कैशलेस अर्थव्यवस्था में लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल चैनलों जैसे डायरेक्ट डेबिट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग और तत्काल भुगतान सेवा (IMPS), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और रियल पेमेंट सिस्टम की मदद से किया जाता है। भारत में टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस)। यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जो ज्यादातर प्लास्टिक या डिजिटल धन पर चलती है और इस प्रकार यह नकदी या कागज के रूप में धन का न्यूनतम उपयोग है। संक्षेप में, यह वित्तीय प्रणाली में आधुनिक तकनीक के व्यापक अनुप्रयोग को संदर्भित करता है।

पारंपरिक भुगतान विधियों का डिजिटलीकरण बैंकिंग उद्योगों, इंटरनेट सेवाओं और मोबाइल उद्योगों का एक क्रांतिकारी विकास है, जो लोगों को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह दुनिया भर में नई तकनीकों और विकास को स्थापित करने का अवसर पैदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप देश का आर्थिक विकास होता है। डिजिटल भुगतान कैशलेस अर्थव्यवस्था का दिल है। डिजिटल भुगतान लेन-देन का एक तरीका है जिसमें विभिन्न प्रकार के डिजिटल मोड का उपयोग करके भुगतान किया जाता है। डिजिटल भुगतान में लेन-देन ऑनलाइन पूरा होता है। डिजिटल भुगतान तब होता है जब उत्पादों को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग से खरीदा जाता है। इस प्रकार की भुगतान पद्धति में नकद या सुविधाजनक तरीकों का कोई उपयोग नहीं है। इसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान भी कहा जाता है। डिजिटल भुगतान बिना ज्यादा समय लिए दुनिया में कहीं भी अपने उपयोगकर्ताओं के व्यापारिक लेनदेन के लिए आर्थिक स्वतंत्रता पैदा करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता लोगों को दुनिया भर में व्यापार करने की अनुमति देती है। वे दुनिया भर में कुछ ही घंटों में सुरक्षित और सुरक्षित लेनदेन के साथ हस्तांतरण या भुगतान स्वीकार करके विश्व स्तर पर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं और यह भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करता है।

100 गुना बढ़ा डिजिटल लेनदेन

सरकार की तरफ से आए आंकड़ों के मुताबिक डिजिटल लेनदेन की संख्या में पिछले नौ वर्षों में 100 गुना इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां महज 127 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए थे, वहीं यह आंकड़ा 2022-23 में (23 मार्च 23 तक) बढ़कर 12,735 करोड़ तक जा पहुंचा है।

कैशलेस अर्थव्यवस्था के लाभ/अवसर

पारदर्शिता और जवाबदेही: कैशलेस सिस्टम के विकास से समानांतर छाया अर्थव्यवस्था (काली अर्थव्यवस्था) पर अंकुश लगता है जो मुख्य रूप से नकदी के आधार पर चलती है। कैशलेस लेनदेन ट्रैक करने योग्य और भौतिक लेनदेन की तुलना में अधिक पारदर्शी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन हमेशा भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए एक डिजिटल प्रूफ फायदेमंद छोड़ देते हैं और इसलिए सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और अनुपालन बनाते हैं। कैशलेस सिस्टम बिना ज्यादा समय लिए स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन-देन के निपटान को गति देता है।

ई-कॉमर्स का बढ़ता चलन: भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था की अवधारणा की शुरुआत के बाद ई-कॉमर्स बाजार को एक नई दिशा मिली है क्योंकि यह 2010 में 4.4 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2015 में लगभग 16 बिलियन डॉलर हो गया है और इसके 2021 तक 76 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले तीन वर्षों में ऑनलाइन खरीदारों की संख्या बढ़कर 90 मिलियन हो गई है। कई ताकतों द्वारा समर्थित ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ रहा है, जैसे ऑनलाइन व्यापारियों द्वारा पेश किया गया मजबूत मूल्य प्रस्ताव, भुगतान प्लेटफॉर्म का प्रसार, वितरण चैनलों को मजबूत करना, होम डिलीवरी आदि। ई-कॉमर्स के बढ़ते विस्तार ने 'डिजिटल भारत' को बढ़ाने में अत्यधिक योगदान दिया है।।

बढ़ा हुआ कर संग्रह: भारत में कैशलेस प्रणाली का एक और बड़ा लाभ यह है कि पिछले कुछ वर्षों में कर चोरी में भारी गिरावट आई है क्योंकि डिजिटल माध्यम से किए गए भुगतान ट्रैक करने के लिए उपयोगी होते हैं और इस तरह सरकारी एजेंसियों के लिए खर्च का ट्रैक रखना और अधिक लाना आसान हो जाता है। कर दायरे में आने वाले लोग जो पहले बड़ी आय होने के बावजूद कर का भुगतान नहीं कर रहे थे।

भारतीय बैंकिंग में तकनीकी नवाचार

डिजिटल तकनीक के अनुप्रयोग ने सभी के लिए बैंकिंग सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता का मार्ग प्रशस्त किया है क्योंकि भीड़भाड़ वाली बैंक शाखाएं, आसानी और सुविधा के साथ 24x7 बैंकिंग सुविधाओं की आवश्यकता, शहरीकरण में वृद्धि, संगठित खुदरा बिक्री, शिक्षा के स्तर में वृद्धि, आय स्तर में वृद्धि, लोगों की बदलती जीवन शैली ग्राहकों ने बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए तकनीकी आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए मजबूर किया है। अब बैंक ग्राहकों को विभिन्न स्तरों पर डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के इच्छुक हैं। भारत में बैंक वर्तमान में तकनीकी बुनियादी ढांचे के विकास पर अपने खर्च का लगभग 15 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं।

सरकार की पहलें: पिछले तीन वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने नवीन विचारों के साथ काम किया और भारत में व्यापक वित्तीय समावेशन लाने के लिए हर घर के लिए बैंक खाता खोलने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी कई पहल की। हमने विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2014 तक 175 मिलियन नए बैंक खाते खोलकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और नवंबर 2016 में यह बढ़कर 255.1 मिलियन हो गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना के दूसरे दौर के तहत 4. 90,000 की पहचान की गई और उन्हें कवरेज के लिए आवंटित किया गया।

बढ़ता हुआ शहरीकरण: पिछले तीन वर्षों में 2% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ शहरीकरण का रुझान लगातार बढ़ रहा है। भारत में 2016 में शहरी आबादी कुल आबादी का 33.136% है। बढ़ता शहरीकरण शिक्षा का स्तर बढ़ा रहा है, प्रयोज्य आय में वृद्धि, जीवन शैली में बदलाव, मोबाइल और इंटरनेट की बढ़ती पैठ, भारतीय ग्राहकों को ई-कॉमर्स की ओर ले जा रहा है, भारत में डिजिटल लेनदेन का प्रसार कर रहा है।

इंटरनेट की बढ़ती पैठ

भारत में पिछले वर्षों से इंटरनेट का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मार्केट रिसर्च फर्म IMRB द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2017 तक मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ता 420 मिलियन तक पहुंच गए। और पांच साल की छोटी अवधि के भीतर डेटा घटक का अनुपात 45% से 65% तक बढ़ गया। पिछले साल रिलायंस जियो की लॉन्चिंग और अन्य टेलीकॉम कंपनियों ने किफायती डेटा पैक के साथ भारत में इंटरनेट की पैठ को लगातार बढ़ाया। इंटरनेट की बढ़ती पैठ के कारण भारतीय बैंक उपभोक्ताओं के अनुभव को बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल करने के लिए नवाचार, सस्ती, उपयोगकर्ता के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग विशेष रूप से पिछले एक साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से पैर जमा रहा है। डिजिटल भुगतान रुपये को छू गया। मई 2016 में 176,001.51 बिलियन की तुलना में मई 2017 में 200.251.32 बिलियन। आरटीजीएस, खुदरा इलेक्ट्रॉनिक सफाई जैसे डिजिटल भुगतान तंत्र। प्रीपेड किस्त भुगतान, कार्ड, एम-वॉलेट। इंटरबैंक और इंट्रा बैंकिंग लेनदेन पिछले एक साल में लगातार गति पकड़ रहे हैं। भारतीय ग्राहक अब आसानी और सुविधा के कारण पारंपरिक शाखा बैंकिंग से इंटरनेट बैंकिंग की ओर जा रहे हैं, लगभग 44% उपयोगकर्ता नेट बैंकिंग का उपयोग कर रहे हैं, यह भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच भुगतान के पसंदीदा तरीके के रूप में उभरा है।

स्मार्ट फोन की पहुंच में वृद्धि: किफायती इंटरनेट डेटा पैक के साथ कम कीमत वाले स्मार्टफोन की उपलब्धता से भारतीय उपभोक्ता फीचर फोन से स्मार्ट फोन की ओर जा रहे हैं। भारत में स्मार्ट फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या 2017 तक 279.24 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। स्मार्ट फोन की मांग टीयर-1 शहरों में संतृप्ति बिंदु तक पहुंच गई है, जबकि टीयर-2 और टीयर-3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगातार बढ़ रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित भारतीय बैंक मोबाइल बेकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और लगभग सभी बैंकों के पास अपने स्वयं के एम-वॉलेट हैं जो उनके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए हैं जो उनके हाथों में भौतिक नकदी ले जाने की बाधाओं को दूर करते हैं। एम-वॉलेट के माध्यम से लेनदेन की मात्रा मई 2016 में 50.31 मिलियन से बढ़कर मई 2016 में 241.72 मिलियन हो गई। मई 2017 यह भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार 380.51% की अभूतपूर्व वृद्धि दर है। स्मार्ट फोन के बढ़ते उपयोग ने भारतीय बैंकिंग को पारंपरिक शाखा आधारित सुविधाओं से तकनीकी रूप से संचालित मोबाइल/इंटरनेट आधारित सुविधा में बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं को अपनाने में भारत दुनिया भर में चौथा स्थान रखता है।

रोजगार के अवसर: कैशलेस अर्थव्यवस्था भारत में रोजगार के नए अवसरों के सृजन का मार्ग प्रशस्त करती है क्योंकि पिछले तीन वर्षों में इंटरनेट की पहुंच लगातार बढ़ रही है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मार्केट रिसर्च फर्म IMRB द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2017 तक मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ता 420 मिलियन तक पहुंच गए और डेटा घटक का अनुपात 45 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गया। पांच साल की छोटी अवधि में। पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। इस तरह की मांग में वृद्धि डिजिटल प्रौद्योगिकी बाजारों में रोजगार के अपार अवसर पैदा करती है।

भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ

डिजिटल साक्षरता: भारत एक ग्रामीण बहुल देश है जहाँ निरक्षरता दर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी अधिक नहीं है। भारत में डिजिटल साक्षरता सिर्फ 10 प्रतिशत है। देश की आधी से ज्यादा आबादी अभी भी कंप्यूटर का उपयोग करना नहीं जानती है। भारत में अभी भी कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं जहां हाई स्पीड नेटवर्क तक पहुंच बहुत मुश्किल है। इसके अलावा, देश में हर कोई इसकी उच्च लागत के कारण इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रहा है। हम डिजिटल साक्षरता के अभाव में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक पारंपरिक शाखा आधारित मॉडल से आभासी रूप से मौजूद कैशलेस अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।

असंगठित अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक स्वदेशी अर्थव्यवस्था है, 50% से अधिक भारतीय आबादी कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगी हुई है, जबकि 2011 में एनएसएस 68 राउंड डेटा के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फसल उत्पादन कार्यबल क्रमशः 75% और 69% है। 2011 में बैंक खाता पैठ केवल 35% थी जो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2014 में बढ़कर 53% हो गई है। भारतीय आबादी के बड़े हिस्से को बैंकिंग सुविधाओं के तहत लाने के उद्देश्य से अगस्त 2014 में प्रधान मंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अगस्त 2017 तक लाभार्थियों की संख्या 29.52 करोड़ थी लेकिन 72% जन धन खाते निष्क्रिय थे, भारत में कैशलेस भुगतान की यह सबसे बड़ी बाधा है

खराब बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: बैंक कैशलेस अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं क्योंकि वे डिजिटल भुगतान प्रणाली का आधार बनाते हैं। हालांकि, कैशलेस अर्थव्यवस्था का आधार बनाने के लिए देश का बैंकिंग ढांचा मांग से मेल खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वित्तीय समावेशन पर सरकार की रिपोर्ट "वित्तीय समावेशन का अवलोकन और प्रगति" बताती है कि 2011 की जनगणना के अनुसार घरों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच केवल 58.7 प्रतिशत है। बड़ी संख्या में बिना बैंक वाली आबादी के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों को शामिल

करना बहुत मुश्किल होगा। आरबीआई की अगस्त 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, प्रति 10,000 लोगों पर एक बैंक शाखा और 5000 लोगों पर एक एटीएम है।

वित्तीय साक्षरता का अभाव: कैशलेस प्रणाली के विकास के लिए वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। हालाँकि, भारत दुनिया की 17.5 प्रतिशत आबादी का घर होने के बावजूद, लगभग 76 प्रतिशत वयस्क आबादी बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं को भी नहीं समझती है और इसके परिणामस्वरूप आबादी का यह बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटल होने के लिए सरकार के अभियान से अलग रहता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में कैशलेस प्रणाली को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।

सीमित बैंकिंग पैठ: सबसे बड़ी चुनौती में सीमित बैंकिंग पैठ, भारत में अपने अन्य समकक्षों की तुलना में शाखाओं की संख्या कम है। वर्तमान में भारत में प्रति 100,000 वयस्क आबादी पर 13.5 वाणिज्यिक बैंक शाखाएं हैं। केवल 40% वयस्क आबादी के पास बैंक खाता है, 13% आबादी के पास डेबिट कार्ड हैं, भारत 600,000 से अधिक गाँवों का देश है, लेकिन केवल 5% गाँवों के निवासियों के पास भारत में वाणिज्यिक बैंक शाखाएँ हैं। 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में 50,554 बैंक शाखाएं थीं। इतनी बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है, जहां 95% भुगतान भौतिक रूप से किए जाते हैं।

प्लास्टिक मनी का खराब प्रवेश: भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे चिंताजनक विशेषता यह है कि कई अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में करेंसी नोटों की संख्या अधिक है। 2012-13 में भारत में 76.47 बिलियन करेंसी नोट चलन में थे जबकि अमेरिका में यह संख्या 34.5 बिलियन थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मुद्रा प्रचलन में थी। 4 नवंबर 2016 को 17.97 ट्रिलियन। इस तरह एक अर्थव्यवस्था में करेंसी नोटों की वृद्धि से मांग और आपूर्ति में अंतर पैदा होता है जिससे मुद्रास्फीति की दर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। असंगठित बाजार में करेंसी नोटों के भौतिक विनिमय के मामले में लेनदेन और व्यय की ट्रैकिंग संभव नहीं है। भारत लेनदेन के लिए बहुत अधिक नकदी का उपयोग करता है। सकल घरेलू उत्पाद में नकदी का अनुपात 2014 में दुनिया में सबसे अधिक-12.42% में से एक है, जबकि चीन में यह 9.47% या ब्राजील में 4% है। इस तरह करेंसी नोटों का बेहिसाब चलन अमीर और गरीब लोगों के बीच एक खाई पैदा करता है क्योंकि यह शेयर बाजार, रियल एस्टेट, मनी लॉन्ड्रिंग आदि में सट्टा गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी बाधा है।

साइबर सुरक्षा मुद्दे: डिजिटल भुगतान में एक और बढ़ती चुनौती साइबर सुरक्षा के मुद्दे हैं, डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने के लिए यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। डिजिटल लेन-देन कई मुद्दों का सामना करता है जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी का जोखिम, गोपनीय जानकारी का रिसाव, साइबर अपराध, मैलवेयर और वायरस के हमलों का जोखिम बढ़ रहा है। डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने के लिए यह सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है जहां डिजिटल साक्षरता बहुत कम है।

कैशलेस की जगह नकदी को प्राथमिकता

नकदी विश्लेषण पर आधारित विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार-'मैकिन्से ग्लोबल पैमेंट्स रिपोर्ट' के अनुसार भारत में वॉल्यूम के हिसाब से लगभग 89% लेनदेन नकदी में होता है। भारत में ई-रिटेल प्लेटफॉर्म पर 65 फीसदी कारोबार कैश ऑन डिलिवरी (सीओडी) से होता है। टियर 1 और टियर 2 शहरों में तो 80% तक ऑर्डर सीओडी पर किए जा रहे हैं। ई-कॉमर्स कंपनियां अगर सीओडी को हतोत्साहित करती हैं तो वॉल्यूम खोने का जोखिम है। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित ग्लोबल फाइंडेक्स के निष्कर्ष भी बताते हैं कि देश की 22 फीसदी वयस्क आबादी के पास कोई बैंक खाता नहीं है, जबकि सिर्फ 35 फीसदी वयस्कों ने 2021 में डिजिटल लेनदेन के लिए अपने बैंक खातों का इस्तेमाल किया। भारत में लेनदेन को लेकर भी लैंगिक असमानता है। इसी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि डिजिटल लेनदेन के मामले में पुरुषों के मुकाबले 13 फीसदी कम महिलाएं रुचि लेती हैं। अप्रैल 2022 में प्रकाशित ग्रामीण वाणिज्य नेटवर्क वनब्रिज (1Bridge) द्वारा की गई फील्ड रिसर्च के अनुसार मात्र 3 से 7 फीसदी ग्रामीण आबादी लेनदेन के लिए किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करती है। एटीएम से कैश विड्रॉल घटा है। करेंसी की खुदरा मांग में यूपीआई की हिस्सेदारी बढ़कर 83% तक हो गई है, जबकि एटीएम से नकद निकासी का हिस्सा घटकर 17% रह गया है। 2016-17 में एटीएम से कैश विड्रॉल (वैल्यू) नॉमिनल जीडीपी का जहां 15.4% था, वहीं 2022-23 में घटकर 12.1% रह गया।

सुझाव

कैशलेस अर्थव्यवस्था की स्थापना के समग्र परिदृश्य को देखते हुए, यह वर्तमान व्यवस्था में फायदेमंद है। आधुनिक तकनीक के युग में कैशलेस अर्थव्यवस्था समय की मांग है। अर्थव्यवस्था में व्यवस्थित विकास के लिए देश का कैशलेस होना न केवल महत्वपूर्ण हो गया है, बल्कि आवश्यक भी है।

प्रभावी परिवर्तन लाने और इस प्रकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास में असमानता को कम करने के लिए ढांचागत सुविधाओं का समान सुधार किया जाना चाहिए। कैशलेस को लेकर केवल योजनाएं और अभियान शुरू करना सार्थक नहीं लगता। इन योजनाओं को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, इन योजनाओं को उपयोगी बनाने के लिए कुछ प्रकार के विपणन उपकरण जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शनियों और शिविरों की स्थापना की जानी चाहिए।

सभी प्रकार के अतिरिक्त शुल्कों को समाप्त करते हुए, ऑनलाइन लेन-देन को यथासंभव सस्ता बनाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग कैश आधारित से कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर जा सकें । कैशलेस प्रणाली के विकास के लिए वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। कैशलेस अर्थव्यवस्था की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए हमें वित्तीय साक्षरता के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए।ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि देश का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करता है। काले धन पर नियंत्रण रखने के लिए भारी निवेश से संबंधित सभी प्रकार के लेन-देन कैशलेस होने चाहिए। धोखेबाजों की संदिग्ध और कपटपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। जो भारत में कैशलेस नीति के विकास में बढ़ती चुनौतियों में से एक है।

निष्कर्ष

कैशलेस अर्थव्यवस्था के विकास से पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और आर्थिक विकास में आसानी होगी। डिजिटल भुगतान चैनलों के उचित तरीकों को अपनाकर भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था हासिल की जा सकती है, जिसके लिए नई और सुरक्षित वित्तीय नीतियों, केंद्रीकृत प्रशासनिक नियंत्रण, बैंकरों, सरकारी एजेंसियों और अन्य निजी सेवा पर नियमित मौद्रिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ाने के लिए, यह सुरक्षित सेवाओं की मांग करता है जैसे भुगतान का तत्काल प्रमाणीकरण, उनके खातों का स्पष्ट विवरण, कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, पैसे पर पूर्ण नियंत्रण, लेनदेन

की प्रक्रिया की पूरी अनिवार्य जानकारी। ग्रामीण क्षेत्रों का डिजीटल परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में पारदर्शिता, लचीलापन, दक्षता, सुविधाजनक, ग्राहक अनुकूल बैंकिंग सुविधाएं लाने के लिए सरकार को पारंपरिक शाखा आधारित मॉडल से तकनीकी रूप से संचालित कैशलेस अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।सभी सरकारी सेवाएं डिजिटल, पारदर्शी तरीके से होंगी केरल को ई-शासित राज्य घोषित किया गया है। साथ ही यह कीर्तिमान बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल दो दशक पहले ही पूरी तरह से साक्षर और ई-साक्षर राज्य बन चुका है। तिरुवनंतपुरम में 'टोटल ई-गवर्नेस केरल की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि पूर्ण ई-गवर्नेस की शुरुआत का मतलब केवल सरकारी कार्यालयों और नागरिकों का नेटवर्क बनाना नहीं है, बल्कि राज्य के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और लोगों को सशक्त बनाना है। इसके जरिए 900 से ज्यादा सेवाएं डिजिटल माध्यम से दी जाएंगी। यही प्रयास अन्य राज्यों में किये जाये तो भविष्य में भारत कैशलेस अर्थव्यवस्था के स्तर को प्राप्त कर सकेगा।

References

1. Hasan A, AtifAman M, Ali MA. Cashless Economy in India: Challenges Ahead. *Journal of Commerce*. 2020; 8(1):21-30.
2. Choudhary A. On Way towards a Cashless Economy Challenges and Opportunities. *International Journal of Business Management & Research* (IJBMR). 2018; 8(2):1-18.
3. Bansal S. Cashless economy: opportunities and challenges in India. *Worldwide J. Multidiscip. Res. Dev*. 2017; 3(9):10-12.
4. Chauhan A. Cashless economy: Opportunities and challenges in India. *Ramanujan International Journal of Business and Research*. 2017; 2:187-194.
5. Singhraul BP, Garwal YS. Cashless economy-challenges and opportunities in India. Pacific Business Review International. 2018; 10(9):54-63.
6. Kaur P. Cash to Cashless Economy: Challenges & Opportunities. *International Journal of,* 360.
7. Kumar A. Demonetization and cashless banking transactions in India. *International Journal of New Innovations in Engineering and Technology*. 2017; 7(3):30-36.
8. Rajak SK. Cash to cashless economy: an Indian perspective. *Int. J. Acad. Res. Dev*. 2017; 2(1):239-241.
9. Gupta R. India towards Cashless Economy. Technological and Managerial Strategies for Next Generation Transformation, 203.
10. Mandal PK. Problems and Prospects of Cashless India. Educreation Publishing, 2017.
11. कुमार अजीत, वित्त मामलों के विशेषज्ञ, आलेख, दैनिक भास्कर 28 मई 2023
12. Saruka, Kalgutkar. Cashless economy in India Present scenario, Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS). 2022; 8(1):124-128.